



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार 14 फरवरी, 2017/25 माघ, 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

ख-अनुभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 जनवरी, 2017

संख्या: जीएडी-बी-(ए) 1-2/2013-I (शिमला).—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की राय है कि ऐसा करना आवश्यक है कि जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में उपमण्डल (नागरिक) रामपुर से सम्पूर्ण कुमारसैन तहसील और उप तहसील कोटगढ़ जिसमें क्रमशः ग्यारह व आठ पटवार वृत्त हैं, को अपवर्जित करके उप

मण्डल (नागरिक), कुमारसैन के नाम से ज्ञात एक नए उप-मण्डल (नागरिक) का सृजन किया जाए ताकि नजदीक के गांवों के सम्बद्ध लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें और जिससे उनको होने वाली असुविधा से निवारित किया जा सके तथा बेहतर प्रशासनिक नियन्त्रण हो सके।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 7 की उप धारा (3) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, उपमण्डल (नागरिक) रामपुर से कुमारसैन तहसील जिसके ग्यारह पटवार वृत्त हैं और उप तहसील कोटगढ़ जिसके आठ पटवार वृत्त हैं, के समस्त क्षेत्र को अपवर्जित करते हैं और जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में एक नए उप-मण्डल (नागरिक) कुमारसैन, जिसका मुख्यालय कुमारसैन में होगा, का तुरन्त प्रभाव से सृजन करते हैं, जिसमें निम्नलिखित पटवार वृत्त समाविष्ट होंगे :-

उप-मण्डल का नाम	जिला	मुख्यालय	सम्मिलित पटवार वृत्त	तहसील / उप तहसील का नाम जहां से अपवर्जित किए गए हैं
कुमारसैन	शिमला	कुमारसैन	1. कुमारसैन 2. कोटीघाट 3. कांगल 4. बनाहर 5. धाला 6. शिवान 7. बड़ागांव 8. जार 9. कचेड़ी 10. मलैन्डी 11. कोटला 12. भुटटी उप तहसील कोटगढ़ 13. शमाथला 14. किरटी 15. कोटगढ़ 16. जरोल 17. जदूण 18. नारकण्डा 19. मधावनी	तहसील कुमारसैन

आदेश द्वारा,
वी०सी०फारका
मुख्य सचिव।

[Authoritative English text of the Himachal Pradesh Government Notification NO. GAB-(A)-1-2/2013-I (Shimla) Dated 6-1-2017 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India.]

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

B-Section

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th January, 2017

No. GAD-B-(A)-1-2/2013-I (Shimla).—Whereas, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary to do so that a new Sub-Division (Civil) to be known as Sub-

Division (Civil) Kumarsain in District Shimla, Himachal Pradesh may be created by excluding the entire Tehsil Kumarsain and Sub Tehsil Kotgarh, having 11 and 8 Patwar Circles respectively, from Sub Division (C) Rampur to provide better services to the concerned people of nearby villages and to avoid inconvenience faced by them and to have the better administrative control.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954) and section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908) read with sub-section (3) of section-7 of the Code of Criminal Procedure 1973, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the High Court of Himachal Pradesh, is pleased to exclude the entire area of Tehsil Kumarsain having 11 patwar circles and Sub Tehsil Kotgarh having 8 patwar circles from Sub Division (C) Rampur and to create a new Sub-Division (Civil) Kumarsain, with its headquarter at Kumarsain, in District Shimla, Himachal Pradesh, which shall consist of the following Patwar Circles with immediate effect :—

Name of Sub Division	District	Head-quarter	Patwar Circles Included	Name of Tehsil / Sub Tehsil from where excluded
Kumarsain	Shimla	Kumarsain	1. Kumarsain 2. Kotighat 3. Kangal 4. Banahar 5. Dhala 6. Shivan 7. Baragaon 8. Jar 9. Kacheri 10. Malendi 11. Kotla 12. Bhutti Sub Tehsil Kotgarh 13. Shamathala 14. Kirti 15. Kotgarh 16. Jarol 17. Jadoon 18. Narkanda 19. Madhawani	Tehsil Kumarsain

By order,
V. C. PHARKA,
Chief Secretary.

सामान्य प्रशासन विभाग
ख-अनुभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 06 जनवरी, 2017

संख्या: जीएडी-बी-(ए) 1-6/2008 (बिलासपुर).—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की राय है कि ऐसा करना आवश्यक है कि जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में उपमण्डल (नागरिक) सदर बिलासपुर से आठ

पटवार वृत्तों वाली सम्पूर्ण श्री नैना देवी जी तहसील को अपवर्जित करके उप मण्डल (नागरिक) श्री नैना देवी जी के नाम से ज्ञात एक नए उप-मण्डल (नागरिक) का सृजन किया जाए ताकि नजदीक के गांवों के सम्बद्ध लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें और जिससे उन्हें होने वाली असुविधा से निवारित किया जा सके तथा बेहतर प्रशासनिक नियन्त्रण हो सके।

अतः, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 7 की उपधारा (3) के साथ पठित, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, उपमण्डल (नागरिक), सदर बिलासपुर से आठ पटवार वृत्तों वाली श्री नैना देवी जी तहसील के समस्त क्षेत्र को अपवर्जित करते हैं और जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में एक नए उप-मण्डल (नागरिक) श्री नैना देवी जी, जिसका मुख्यालय स्वारघाट में होगा, का तुरन्त प्रभाव से सृजन करते हैं, जिसमें निम्नलिखित पटवार वृत्त समाविष्ट होंगे :-

उप-मण्डल का नाम	जिला	मुख्यालय	सम्मिलित पटवार वृत्त	तहसील/उपमण्डल का नाम जिससे अपवर्जित किए गए हैं
श्री नैना देवी जी	बिलासपुर	स्वारघाट	1. दभेटा श्री 2. जगातखाना 3. स्वाहण 4. बैहल 5. श्री नैना देवी जी 6. भाखड़ा 7. समतैहण 8. दभटमाजरी	नैना देवी जी (सदर बिलासपुर)

आदेश द्वारा,
वी० सी० फारका,
मुख्य सचिव।

[Authoritative English text of the Himachal Pradesh Government Notification NO. GAB-(A)-1-6/2008 (Bilaspur) Dated 6-1-2017 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

**GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
B-Section**

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th Janaury, 2017

No. GAD-B-(A)-1-6/2008 (Bilaspur).—Whereas, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary to do so that a new Sub-Division (Civil) to be known as Sub-Division (Civil) Shri Naina Devi Ji in District Bilaspur, Himachal Pradesh may be created by excluding the entire Tehsil Shri Naina Devi Ji, having 8 Patwar Circles from Sub Division (C) Sadar Bilaspur to provide better services to the concerned people of nearby villages and to avoid inconvenience faced by them and to have the better administrative control.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954) and section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908) read with sub-section (3) of section-7 of the Code of Criminal Procedure 1973, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the High Court of Himachal Pradesh, is pleased to exclude the entire area of 8 Patwar Circle of Tehsil Shri Naina Devi Ji from Sub-Division (C) Sadar Bilaspur and to create a new Sub-Division (Civil) Shri Naina Devi Ji with its headquarter at Swarghat in District Bilaspur, Himachal Pradesh, which shall consist of the following Patwar Circles with immediate effect :—

Name of Sub Division	District	Head-quarter	Patwar Circles Included	Name of Tehsil/ Sub. Div. from where excluded
Shri Naina Devi Ji	Bilaspur	Swarghat	1. Dabheta 2. Jagatkhana 3. Swahan 4. Behal 5. Shri Naina Ji 6. Bhakra 7. Samtehan 8. Dabhatmajari	Shri Naina Devi Ji (Sadar Bilaspur)

By order,
V. C. PHARKA,
Chief Secretary.

सामान्य प्रशासन विभाग
ख-अनुभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 जनवरी, 2017

संख्या: जीएडी-बी-(ए) 1-5/2013-III (कांगड़ा).—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की राय है कि ऐसा करना आवश्यक है कि जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में उपमण्डल (नागरिक) कांगड़ा से सम्पूर्ण नगरोटा बगवां तहसील और तहसील बडोह, जिसमें क्रमशः बीस और पंद्रह पटवार वृत्त हैं, को अपवर्जित करके उप मण्डल (नागरिक) नगरोटा बगवां के नाम से ज्ञात एक नए उप-मण्डल (नागरिक) का सृजन किया जाए, ताकि नजदीक के गांवों के सम्बद्ध लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें और जिससे उनको होने वाली असुविधा से निवारित किया जा सके तथा बेहतर प्रशासनिक नियन्त्रण हो सके।

अतः, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 7 की उप धारा (3) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, उपमण्डल (नागरिक), कांगड़ा से तहसील नगरोटा बगवां जिसके बीस पटवार वृत्त हैं, और तहसील बडोह जिसके पन्द्रह पटवार वृत्त हैं, के समस्त क्षेत्र को अपवर्जित करते हैं और जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में एक नए उप-मण्डल (नागरिक) नगरोटा बगवां,

जिसका मुख्यालय नगरोटा बगवां में होगा, का तुरन्त प्रभाव से सृजन करते हैं, जिनमें निम्नलिखित पटवार वृत्त समाविष्ट होंगे :-

उप-मण्डल का नाम	जिला	मुख्यालय	सम्मिलित पटवार वृत्त	तहसील/उप तहसील का नाम जहां से अपवर्जित किए गए हैं।
नगरोटा बगवां	कांगड़ा	नगरोटा बगवां	<ol style="list-style-type: none"> 1. पठियार 2. अम्बाड़ी 3. हटवास 4. कवाड़ी 5. चाहड़ी 6. नगरोटा बगवां 7. मसल 8. घोड़व 9. वड़ाई 10. मुन्दला 11. झिकली कोठी 12. बग 13. होस्टी 14. गुजरेहड 15. मुमता 16. अमताराड 17. रजियाना 18. रौखर 19. सिंहून्ड 20. धंलू 21. थान तहसील बडोह 22. गारनी 23. देहरू 24. कनेहड 25. दनौआ 26. भातर 27. झराल 28. मोरठ 29. सरौती खास 30. मंगरेला 31. संदू 32. संधी 33. हार-I 34. हार-II 35. बलोल 	तहसील नगरोटा बगवां

आदेश द्वारा,
वी० सी० फारका,
मुख्य सचिव।

[Authoritative English text of the Himachal Pradesh Government Notification NO. GAB (A)-1-5/2013-III (Kangra) Dated 4-1-2017 as required under clause(3) of article 348 of the Constitution of India.]

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
B-Section

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th January, 2017

No. GAD-B-(A)-1-5/2013-III (Kangra).—Whereas, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary to do so that a new Sub-Division (Civil) to be known as Sub-Division (Civil) Nagrota Bagwan in District Kangra, Himachal Pradesh may be created by excluding the entire Tehsil Nagrota Bagwan and Tehsil Baroh, having 20 and 15 Patwar Circles respectively, from Sub Division (C) Kangra, to provide better services to the concerned people of nearby villages and to avoid inconvenience faced by them and to have the better administrative control.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954) and section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908) read with sub-section (3) of section-7 of the Code of Criminal Procedure 1973, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the High Court of Himachal Pradesh, is pleased to exclude the entire area of Tehsil Nagrota Bagwan having 20 patwar circles and Tehsil Baroh having 15 patwar circles from Sub Division (C) Kangra and to create a new Sub-Division (Civil) Nagrota Bagwan with its headquarter at Nagrota Bagwan in District Kangra, Himachal Pradesh, which shall consist of the following Patwar Circles with immediate effect :—

Name of Sub Division	District	Head-quarter	Patwar Circles Included	Name of Tehsil / Sub Tehsil from where excluded
Nagrota Bagwan	Kangra	Nagrota Bagwan	1. Pathiar 2. Ambari 3. Hatwas 4. Kawari 5. Chahri 6. Nagrota Bagwan 7. Massal 8. Ghorab 9. Barai 10. Mundla 11. Jhikli Kothi 12. Bag 13. Honsti 14. Gujrehra 15. Mumta 16. Amtrar 17. Rajiana 18. Rounkhar 19. Sihund 20. Dhaloon	Tehsil Nagrota Bagwan

			21. Than Tehsil Baroh 22. Garni 23. Dehru 24. Kanehr 25. Danoya 26. Bhater 27. Jhral 28. Morath 29. Sarotri Khas 30. Mangrela 31. Sandu 32. Sunhi 33. Har First 34. Har Second 35. Balol	
--	--	--	--	--

By order,
V. C. PHARKA,
Chief Secretary.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 2nd February, 2017

No. HHC/GAZ/14-353/2015.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 09 days' earned leave *w.e.f.* 02-02-2017 to 10-02-2017 with permission to suffix Second Saturday and Sunday falling on 11-02-2017 and 12-02-2017 in favour of Shri Prateek Gupta, Civil Judge-*cum*-JMJC (II), Dehra, District Kangra, H.P.

Certified that Shri Prateek Gupta is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Prateek Gupta would have continued to hold the post of Civil Judge-*cum*-JMJC (II), Dehra, District Kangra, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 3rd February, 2017

No. HHC/GAZ/14-303/2009.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex-post facto* sanction of 03 days earned leave *w.e.f.* 26-12-2016 to 28-12-2016 and 02 days commuted leave

for 29-12-2016 and 30-12-2016 in favour of Ms. Vijay Lakshmi, Senior Civil Judge-cum-ACJM, Amb, District Una, H.P.

Certified that Ms. Vijay Lakshmi has joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Vijay Lakshmi would have continued to hold the post of Senior Civil Judge-cum-ACJM, Amb, District Una, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 7th February, 2017

No. HHC/Estt. 3 (339)/92-I.—24 days earned leave on and *w.e.f.* 09-02-2017 to 04-03-2017, with permission to suffix Sunday falling on 05-03-2017, is hereby sanctioned in favour of Shri Ram Lal Verma, Secretary of this Registry.

Certified that Shri Ram Lal Verma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Ram Lal Verma would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 7th February, 2017

No. HHC/Estt. 3 (258)/87-I.—20 days earned leave on and *w.e.f.* 27-02-2017 to 18-03-2017, with permission to prefix Sunday, 2nd batch special casual leave and Sunday on and with effect from 05-02-2017 to 26-02-2017 and suffix Sunday falling on 19-03-2017, is hereby sanctioned in favour of Shri Naresh Kumar Sharma, Court Master of this Registry.

Certified that Shri Naresh Kumar Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Naresh Kumar Sharma would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 2nd February, 2017

No. HHC/Admn. 6 (23)/74-XV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H. P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Senior Civil Judge-cum-ACJM, Dehra, District Kangra, H. P. as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge-cum-JMIC(II), Dehra, H. P. and also the Controlling Officer for the purpose of T. A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid court under Major head "2014 Administration of Justice" during the earned leave period of Shri Prateek Gupta, Civil Judge-cum-JMIC(II), Dehra, District Kangra, H. P. w.e.f. 02-02-2017 to 10-02-2017 with permission to suffix Second Saturday and Sunday falling on 11-02-2017 and 12-02-2017 or until he returns from leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 फरवरी, 2017

संख्या: होम बी(बी)3-2/95-अग्नि.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा विभाग में **प्रभागीय अग्निशमन अधिकारी/अग्नि निवारण अधिकारी, वर्ग-II (अराजपत्रित)** तकनीकी सेवाएं के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा विभाग, प्रभागीय अग्निशमन अधिकारी/अग्नि निवारण अधिकारी, वर्ग-II (अराजपत्रित) तकनीकी सेवाएं भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 है ।

(2) ये नियम, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. निरसन और व्यावृत्तियां.—(1) अधिसूचना संख्या होम-बी-(बी) 3-2/95, तारीख 25-11-2013 द्वारा अधिसूचित और समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा विभाग प्रभागीय

अग्निशमन अधिकारी/अग्नि निवारण अधिकारी, (वर्ग-II) (अराजपत्रित) तकनीकी सेवाएं भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2(1)के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव (गृह)।

उपाबन्ध—‘क’

हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा विभाग में सेवा में प्रभागीय अग्निशमन अधिकारी/अग्नि निवारण अधिकारी, वर्ग- II (अराजपत्रित) पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम ।

1. पद का नाम.—प्रभागीय अग्निशमन अधिकारी/अग्नि निवारण अधिकारी ।
2. पद की संख्या.—3 (तीन) ।
3. वर्गीकरण.—वर्ग-II (अराजपत्रित) तकनीकी सेवाएं ।
4. वेतनमान (i) नियमित पदधारियों के लिए पे बैण्ड.—10,300—34800 रूपए जमा 4200/— रूपए ग्रेड पे ।
(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.— स्तंभ संख्या 15—क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 14,500/—रूपए प्रतिमास ।
5. “चयन” पद अथवा “अचयन” पद.—चयन ।
6. सीधी भर्ती के लिए आयु:—18 से 45 वर्ष ।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है:

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेसन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर

निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे:

टिप्पणी.— सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.—(क) अनिवार्य अर्हता.—(1) राष्ट्रीय अग्निशमन सेवाएं महाविद्यालय नागपुर से बी.ई. (फायर इंजीनियरिंग) की डिग्री प्राप्त की हो।

या

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम स्नातक या इसके समतुल्य और राष्ट्रीय अग्निशमन सेवाएं महाविद्यालय, नागपुर से प्रभागीय अधिकारी कोर्स उत्तीर्ण किया हो।

(ii) राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार/पब्लिक सेक्टर उपक्रम/नगरपालिका समितियों द्वारा चलाए जा रहे अग्निशमन केन्द्रों में अग्निशमन केन्द्र अधिकारी के रूप में कम से कम तीन वर्ष की सेवा की हो।

2. न्यूनतम शारीरिक मानदण्ड:

लम्बाई — 165 सेंटीमीटर

छाती — 80 सेंटीमीटर

और फुलाकर 85 सेंटीमीटर तक

वजन — 52 किलोग्राम

दृष्टि — 6/6 बिना चश्मे के।

(ख) वांछनीय अर्हताएं.—हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं:

आयु.—लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हताएं.—हां, जैसी कि नीचे स्तम्भ संख्या 11 में विहित की गई है।

9. परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.—(i) सीधी भर्ती की दशा में:

(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए, विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।

(ख) संविधा के आधार पर, धारणाधिकार आधार पर नियुक्ति, सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनः नियोजन और आमलेन की दशा में परीक्षा अवधि नहीं होगी।

(ii) प्रोन्नति की दशा में दो वर्ष या एक समूह से दूसरे समूह में प्रोन्नति की दशा में पद पर सीधी भर्ती के लिए विहित परीक्षा, यदि कोई हो।

10. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद(पदों) की प्रतिशतता.—शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगा.—अग्निशमन केन्द्र अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय नागपुर से प्रभागीय अग्निशमन अधिकारी का कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो और विहित कोर्स को पूर्ण करने के पश्चात जिनका 2 वर्ष का नियमित सेवाकाल हो या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके दो वर्ष का नियमित सेवाकाल हो:

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम/कठिन क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्वीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी:

परन्तु यह और कि उपरोक्त परन्तुक(1), कठिन ग्रामीण क्षेत्र में तैनाती/स्थानान्तरण के सिवाए उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति की दशा में लागू नहीं होगी:

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम/कठिन क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, तो ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (कांडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जायेगा।

स्पष्टीकरण I:—उपरोक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम/कठिन और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में “कार्यकाल” से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए, ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण II:—उपरोक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:—

1. जिला लाहौल एवं स्पिति।
2. चम्बा जिलाका पांगी और भरमौर उप-मण्डल।
3. रोहडू उपमण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीश, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. जिला कुल्लू का पन्द्रह बीस परगना।
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
7. जिला किन्नौर।
8. सिरमौर जिला में, उप तहसील कमरु के काठवाड और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।

9. मण्डी जिला में, करसोग तहसील का खनयोल-बगडा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी घनहार, थाची, बागगी सोमगाड और खोलानाल, पटवार वृत्त, पदर तहसील के झारवाड, कुटगढ, ग्रामन, देवगढ, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भडवानी, हस्तपुर, घमरेहड और भटेढ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूनी, कालीपार, मानगढ, थाच-बगडा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दर नगर तहसील का बटवाडा पटवार वृत्त ।

स्पष्टीकरण III.—उपरोक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:—

- (I) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से बीस किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान ।
- (II) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहां के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3(तीन) किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है ।
- (III) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना अपने गृह नगर या गृह नगर क्षेत्र के साथ लगता 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हों) के आधार पर उपयुक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-2 प्रवर्ग/पद/कांडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखें जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदाधिकारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम आर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो होगी:

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेजन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के नियम के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तदधीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेजन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किए गए हो और तदधीन वरीयता लाभ दिए गए हों इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् स्थाईकरण के फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.—विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग के सदस्य द्वारा की जाएगी ।

13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण से पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

15.क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अधीन की जाएंगी ।

(I) संकल्पना.—(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश अग्निशमन विभाग में प्रभागीय अग्निशमन अधिकारी/अग्नि निवारण अधिकारी को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी ।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.—प्रधान सचिव (गृह) रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यक्ष को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा ।

(ग) चयन, इन भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(II) संविदात्मक संविदात्मक उपलब्धियां.—संविदा के आधार पर नियुक्त प्रभागीय अग्निशमन अधिकारी/अग्नि निवारण अधिकारी को 14,500/—रुपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ोतरी की जाती है तो पश्चात्तवर्ती वर्ष(वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 435/— रुपए की रकम (पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.—प्रधान सचिव (गृह) हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

चयन प्रक्रिया.—संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण से पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या

व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर / पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.—जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.—अभ्यर्थी को चयन के पश्चात्, इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-‘ख’ के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VII) निबन्धन और शर्तें.—(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 14,500/—रुपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 435/— रुपए की दर से (पे-बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहवद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यबसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी ।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी । संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किए जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा ।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य(ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवाधिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा । तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य(ड्यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी, प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी । ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे कि एफ0आर0एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्जित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.— लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

उपाबंध—“ख”

प्रभागीय अग्निशमन अधिकारी/अग्नि निवारण अधिकारी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक अग्निशमन के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा /करार का प्ररूप

यह करार श्री/ श्रीमती -----पुत्र/पुत्री श्री----- निवासी----- संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य निदेशक अग्निशमन सेवाएं हिमाचल प्रदेश शिमला (जिसे इसमें इसके पश्चात द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ----- को किया गया।

“द्वितीय पक्षकार” ने उपरोक्त ‘प्रथम पक्षकार’ को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने प्रभागीय अग्निशमन अधिकारी / अग्नि निवारण अधिकारी के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार प्रभागीय अग्निशमन अधिकारी/अग्नि निवारण अधिकारी के रूप में -----से प्रारम्भ होने और ----- को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस, अर्थात् ----- दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा:

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण /नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ----- रूपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. प्रभागीय अग्निशमन अधिकारी/अग्नि निवारण अधिकारी संविदात्मक एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भवात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाए, किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा तथा आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य(ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर हो तो उसके नियमितकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियंत्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण के लिए पात्र होगा, जहां प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था, प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाना चाहिए।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी अधिकारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदात्मक पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप, प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के साक्षियों की उपस्थिति में इसके सर्वप्रथम उल्लिखित दिन, मास और वर्ष को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में:

1. _____
नाम-----
पता-----

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में :

1
नाम.....
पता.....

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English text of this department's Notification No. Home-B(B)3-2/95-Fire dated 25.11.2013 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 7th Feb., 2017

No. Home-B(B)3-2/95-Fire.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Divisional Fire Officer/Fire Prevention Officer Class-II (Non-Gazetted) Technical Services in the Department of Fire services, Himachal Pradesh, as per Annexure –“A” attached to this notification namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Fire Services Department for the post of Divisional Fire Officer/Fire Prevention Officer (Class-II) (Non- Gazetted) Technical Services Recruitment and Promotion Rules, 2017.

(2) These rules shall come into force from date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal & Savings.—(1) The Himachal Pradesh Fire Services Department for the post of Divisional Fire Officer/Fire Prevention Officer Class-II (Non-Gazetted) Technical Services Recruitment and Promotion Rules, 2013 notified vide notification Home-B(B)3-2/95-Fire dated 25-11-2013 as amended from time to time are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any appointment made or any thing done or any action taken under the relevant rules, so repealed under Rule, 2 (1) supra shall be deemed to have been validly made done or taken under these rules.

By order,
Sd/-

Principal Secretary(Home).

ANNEXURE “A”

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF DIVISIONAL FIRE OFFICER/FIRE PREVENTION OFFICER (NON GAZETTED) CLASS-II IN THE DEPARTMENT OF FIRE SERVICES, HIMACHAL PRADESH.

1. Name of post.— Divisional Fire Officer/Fire prevention Officer.

2. Number of post(s).—3(Three).

3. Classification.— Class-II (Non Gazetted) Technical Services.

4. Scale of pay.— (i) Pay Band for regular incumbents: Rs.10300-34800+Rs. 4200/- Grade Pay .

(ii) Emoluments for Contract employees: Rs. 14500/-P.M.as per details given in Column No.15-A.

5. Whether “Selection” post or “non-selection” post.—Selection.**6. Age for direct recruitment.—**18 to 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on ad-hoc or on contract basis :

Provided further that if a candidate appointed on ad-hoc basis or on contract basis had become overage on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such ad-hoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for scheduled Castes/Scheduled Tribes/ other wackward classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who are /were subsequently appointed by such Corporation/ Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporation/Autonomous Bodies.

Note: Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post (s) is/are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchanges, as the case may be.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).—
Essential Qualification.— 1. B.E. (Fire Engineering) Degree from the National Fire Service College, Nagpur.

OR

(i) At least graduate from a recognized University or its equivalent, and should have passed Divisional Officer’s Course from the National Fire Service College, Nagpur.

(ii) Should have served as Station Fire Officer at least 03 years run by the State Govt./Central Govt./Public Sector Under Taking/Municipal Committees.

2. Minimum Physical Standard:

Height - 165 Cms
Chest- 80 Cms
with expansion

upto 85 Cms..
Weight - 52 Kg.
Eye sight- 6/6
without glasses.

Desirable Qualifications.—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promote(s).—*Age.*—Not applicable.

Essential Qualification.— Yes, as prescribed against Col. No. 11 below.

9. Period of probation, if any.— (i) Direct Recruitment: (a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing .

(b) No probation in the case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.

(ii) Promotion.—Two year or the period of probation prescribed for the direct recruitment to the post, if any, in the case of promotion from one group to another.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/secondment /transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—100% by promotion failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion/secondment/transfer, grade from which promotion/secondment/transfer is to be made.—By promotion from amongst Station Fire Officers who have successfully completed the Divisional Fire officer course from National Fire Service College, Nagpur, with 02 (two) years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade after completion of the prescribed course.

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation except posting /transfer in remote /rural area . However, this condition of five shall not be applicable in case of promotion :

Provided further that Officers/Officials who has not served atleast one tenure in Tribal/difficult/Hard areas and remote/rural area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I.—For the purpose of proviso I supra the “term” in Tribal/Difficult/ hard areas/remote/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/convenience .

Explanation II.—For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—

1. District Lahaul & Spiti.
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.

3. Dodra Kwar Area of Rohru Sub-Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
6. Bara Bhargal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
7. District Kinnaur.
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada- Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

Explanation III.— For the purpose of proviso (I) Supra the remote/Rural Areas shall be as under:

- (i) All stations beyond the radius of 20 Kms. from sub Division/Tehsil headquarter.
- (ii) All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District Head quarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3 (three) Kms.
- (iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category.

(II) In all cases of promotion , the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:

(1) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service(including the service rendered on adhoc basis followed by the regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category /post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three days years or that prescribed in the Recruitment & Promotion for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration of such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of rules-3 of ExServicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment /promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules :

Provided that inter-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—D.P.C. to be presided over by the Chairman, Himachal Pradesh Public Service Commission or a Member, thereof to be nominated by him.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for direct recruitment.—A candidate for appointment to any service Or post must be a Citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.— Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/ personality test, if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/ written or practical test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/ other recruiting agency/ authority as the case may be.

15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Divisional Fire Officer/Fire Prevention Officer in the Department of Fire Services, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for further extension /renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/ extended.

(b) *POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC.*— The Principal Secretary (Home) to the Government of Himachal Pradesh, after obtaining the approval of the Government for filling up the vacant post(s) on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.

(c) The Selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Recruitment & Promotion Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Divisional Fire Officer/Fire Prevention Officer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed amount @ Rs.14500/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band +grade pay). An amount of Rs. 435/- (3 % of the minimum of the pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Principal Secretary (Home) to the Government of Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.— Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment shall be made on the basis of interview/personality test, if the Himachal Pradesh Public Services Commission so consider necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test(objective type) /written test or practical test or physical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Public Service Commission.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.

(VI) AGREEMENT.— After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-‘B’ appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 14500/- P.M/- (which shall be equal to minimum of the pay band +grade pay). The contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 435/- (3 % of the minimum of pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/ selection scales etc will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract appointee will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 10 day's Medical Leave and 5 days Special Leave. A female contract appointee shall also be entitled for Maternity Leave not exceeding 45days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of Medical Certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and special leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for unauthorized absence from duty were beyond his/her control on Medical Grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization what the incumbent shall have to intimate the controlling authorities in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty :

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidates pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate shall be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter part officials at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Caste/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable.

18. Powers to Relax.—Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or posts(s).

ANNEXURE-‘B’

FORM OF CONTRACT/ AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE DIVISIONAL FIRE OFFICER/FIRE PREVENTION OFFICER AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH, THROUGH THE DIRECTOR, FIRE SERVICES, HIMACHAL PRADESH

This agreement is made on thisday of..... In the year.....Between.....Sh./Smt.....S/o/D/o Shri.....R/O... ..Contract appointee (hereinafter called the “FIRST PARTY”) AND THE GOVERNOR, HIMACHAL PRADESH, THROUGH THE DIRECTOR FIRE SERVICES, HIMACHAL PRADESH, SHIMLA (here-in-after referred to as the SECOND PART).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid “FIRST PARTY” and the “FIRST PARTY” has agreed to serve as a DIVISIONAL FIRE OFFICER/FIRE PREVENTION OFFICER on contract basis on the following terms and conditions:—

1. That the “FIRST PARTY” shall remain in the service of the “SECOND PARTY” as a Divisional Fire Officer/Fire Prevention Officer for a period of 1 year commencing on day ofand ending on the day ofIt is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. onand information notice shall not be necessary:

Provided that for further extension /renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/ extended.

2. The contractual amount of the "FIRST PARTY" will be Rs..... per month.
3. The service of "FIRST PARTY" will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
4. Contractual DIVISIONAL FIRE OFFICER/FIRE PREVENTION OFFICER will be entitled for one day's casual leave after putting in one month service. However, the contract employee will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 10 day's Medical Leave and 5 days special leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service in case of miscarriage including abortion, on production of Medical Certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and special leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on Medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render of temporary unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS THE FIRST PARTY AND SECOND PARTY have here in to set their hands the day month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _____

 (Name and full Address) (Signature of the FIRST PARTY)

2. _____

 (Name and full Address) (Signature of the SECOND PARTY)

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 8th February, 2017

No. Home-B (E) 3-17/2003-Loose.—In partial modification of this Department notification of even number dated 25-10-2016, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh, is pleased to nominate Hon'ble Mr. Justice Sureshwar Thakur, Judge, High Court of Himachal Pradesh as Member of Board of Governors of Himachal Pradesh Judicial Academy with immediate effect, in place of Hon'ble Mr. Justice P. S. Rana, who has demitted the office on His Lordship's appointment as President of Himachal Pradesh Consumer Disputes Redressal Commission.

By order,
 Sd/-
Principal Secretary (Home).

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 14 फरवरी, 2017

संख्या: एल0एल0आर0-डी0(6)-27 / 2016-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 09-02-2017 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 24) को वर्ष 2017 के अधिनियम संख्यांक 2 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,
 (डा० बलदेव सिंह),
 प्रधान सचिव (विधि)।

**हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन)
अधिनियम, 2016**

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 9 फरवरी, 2017 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 9) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम।**

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

(2) यह प्रथम सितम्बर, 2016 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. धारा 3 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ii) में, “अनुसूची 2 की क्रम संख्या 1 (क)” शब्दों, अंकों और चिन्हों से पूर्व “जब ऐसा माल विनिर्माण, प्रसंस्करण, संपरिवर्तन, फुटकर काम, संमजन, पैकिंग या ऊर्जा के आबद्ध उत्पादन में प्रयुक्त किया जाता है तो” शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

3. धारा 8 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु जब ऐसा माल विनिर्माण, प्रसंस्करण, संपरिवर्तन, फुटकर काम, संमजन, पैकिंग या ऊर्जा के आबद्ध उत्पादन में प्रयुक्त किया जाता है तो अनुसूची 2 की क्रम संख्या 1 (क) में वर्णित माल पर कोई छूट (सैट-ऑफ) नहीं होगी।”।

4. 2016 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 3 का निरसन और व्यावृत्तियाँ.—(1) हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2016 का एतद्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अनुसार की गई समझी जाएगी।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 2 OF 2017

**THE HIMACHAL PRADESH TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREA
(SECOND AMENDMENT) ACT, 2016**

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 9TH FEBRUARY, 2017)

AN

ACT

*further to amend the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010
(Act No. 9 of 2010).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area (Second Amendment) Act, 2016.

(2) It shall be deemed to have come into force on 1st day of September, 2016.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010 (hereinafter referred to as the “principal Act”), in sub-section (4), in clause (ii), after the words and signs “of Schedule-II”, the words and signs “when such goods are used in manufacturing, processing, conversion, job-work, assembling, packing or captive generation of power” shall be inserted.

3. Amendment of section 8.—In section 8 of the principal Act, after sub-section (2), the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided that no set off shall be available on goods mentioned at Serial No.1(a) of Schedule-II when such goods are used in manufacturing, processing, conversion, job-work, assembling, packing or captive generation of power.”.

4. Repeal of H. P. Ordinance No. 3 of 2016 and savings.—(1) The Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area (Second Amendment) Ordinance, 2016 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

